challenge of nation-The building, covered in the last chapter, was accompanied by challenge of instituting democratic politics. Thus, electoral competition among political parties began immediately after Independence. In this chapter, we look at the first decade of electoral politics in order to understand

- the establishment of a system of free and fair elections;
- the domination of the Congress party in the years immediately after Independence; and
- the emergence of opposition parties and their policies.

पिछले अध्याय में हमने राष्ट-निर्माण की चुनौती के बारे में चर्चा की थी। राष्ट-निर्माण की चुनौती के तुरंत बाद हमारे सामने एक और चुनौती लोकतांत्रिक राजनीति की जमीन तैयार करने की थी। राजनीतिक दलों के बीच चुनावी प्रतिस्पर्धा आजादी के तुरंत बाद शुरू हो गई थी। इस अध्याय में हम चुनावी राजनीति के पहले दशक की बातों पर गौर करेंगे। इस चर्चा से हम निम्नलिखित बातों को समझ सकेंगे:

- ▶एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव-प्रणाली की स्थापना;
- > आजादी के बाद के शुरुआती सालों में कांग्रेस पार्टी का दबदबा;
- >विपक्षी दलों और उनकी नीतियों का उद्भव।

Challenge building democracy You now have an idea of the difficult circumstances in which independent India was born. You have read about the serious challenge of nation-building that confronted the country right in the beginning. **Faced with such serious** challenges, leaders in many other countries of the world decided that their country could not afford to have democracy. They said that national unity was their first priority and that democracy will introduce differences and conflicts.

लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती

आपको अब अंदाज़ा लग चुका होगा कि स्वतंत्र भारत का जन्म किन कठिन परिस्थितियों में हुआ। अपने देश के सामने श्रुग्आत से ही राष्ट-निर्माण की चुनौती थी और इन गंभीर चुनौतियों के बारे में आप पढ चुके हैं। एसी चुनौतियों की चपेट में आकर कई अन्य देशों के नेताओं ने फ़ैसला किया कि उनके देश में अभी लोकतंत्र को नहीं अपनाया जा सकता है। इन नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय एकता हमारी पहली प्राथमिकता है और लोकतंत्र को अपनाने से मतभेद और संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। उपनिवेशवाद के चंगुल से आज़ाद हुए कई देशों में इसी कारण अलोकतांत्रिक शासन-व्यवस्था कायम हुई।

Therefore many of the countries that gained freedom from colonialism experienced nondemocratic rule. It took various forms: nominal democracy but effective control by one leader, one party rule or direct army rule. Nondemocratic regimes always started with a promise of restoring democracy very soon. **But once they** established themselves, it was very difficult to dislodge them.

इस अलोकतांत्रिक शासन-व्यवस्था के कई रूप थे। कहीं पर थोड़ा-बहुत लोकतंत्र रहा, लेकिन प्रभावी नियंत्रण किसी एक नेता के हाथ में था तो कहीं पर एक दल का शासन कायम हुआ और कहीं-कहीं पर सीध-सीधे सेना ने सत्ता की बागडोर सँभाली। अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं की शुरुआत इस वायदे से हुई कि जल्दी ही लोकतंत्र कायम कर दिया जाएगा। बहरहाल, एक बार कहीं अलोकतांत्रिक शासन के पाँव जम गए तो फिर उसे बदल पाना मुश्किल होता गया।

The conditions in India were not very different. **But the leaders of the** newly independent India decided to take the more difficult path. Any other path would have been surprising, for our freedom struggle was deeply committed to the idea of democracy. Our the critical role of politics in any democracy. They did not see politics as a problem; they saw it as a way of solving the problems. Every society needs to decide how it

will govern and regulate

भारत में भी परिस्थितियां बहुत अलग नहीं थीं, लेकिन आज़ाद भारत के नेताओं ने अपने लिए कहीं ज्यादा कठिन रास्ता चुनने का फ़ैसला किया। नेताओं ने कोई और रास्ता चुना होता तो वह आश्चर्य की बात होती क्योंकि हमारे स्वतंत्रता-संग्राम की गहरी प्रतिबद्धता लोकतंत्र से थी। हमारे नेता लोकतंत्र में राजनीति की निर्णायक भूमिका को लेकर सचेत थे। वे राजनीति को समस्या के रूप में नहीं देखते थे; leaders were conscious of वे राजनीति को समस्या के समाधान का उपाय मानते थे। हर समाज के लिए यह फ़ैसला करना ज़रूरी होता है कि उसका शासन कैसे चलेगा और वह किन कायदे-कानूनों पर अमल करेगा। चुनने के लिए हमेशा कई नीतिगत विकल्प मौजूद होते हैं।

There are always different policy alternatives to choose from. There are different groups with different and conflicting aspirations. How do we resolve these differences? Democratic politics is an answer to this question. While competition and power are the two most visible things about politics, the purpose of political activity is and should be deciding and pursuing public interest. This is the route our leaders decided to take.

किसी भी समाज में कई समूह होते हैं। इनकी आकांक्षाएँ अकसर अलग-अलग और एक-दूसरे के विपरीत होती हैं। एसे में हम विभिन्न समूहों के हितों के आपसी टकराव से कैसे निपट सकते हैं? इसी सवाल का जवाब है-लोकतांत्रिक राजनीति। सत्ता और प्रतिस्पर्धा राजनीति की दो सबसे ज्यादा जाहिर चीज़ें हैं। लेकिन. राजनीतिक गतिविधि का उद्देश्य जनिहत का फैसला करना और उस पर अमल करना होता है और एसा होना भी चाहिए। हमारे नेताओं ने इसी रास्ते को चुनने का फैसला किया।

Last year you studied how our Constitution was drafted. You would remember that the **Constitution was adopted** on 26 November 1949 and signed on 24 January 1950 and it came into effect on 26 January 1950. At that time the country was being ruled by an interim government. It was now necessary to install the first democratically elected government of the country. The Constitution had laid down the rules, now the machine had to be put in place. Initially it was thought that this was only a matter of a few months

पिछले साल आपने पढ़ा कि हमारा संविधान कैसे बना। आपको याद होगा कि हमारा संविधान 26 नवम्बर 1949 को अंगीकृत किया गया और 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर हुए। यह संविधान 26 जनवरी 1950 से अमल में आया। उस वक्त देश का शासन अंतरिम सरकार चला रही थी। वक्त का तकाजा था कि देश का शासन लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार द्वारा चलाया जाए। संविधान ने नियम तय कर दिए थे और अब इन्हीं नियमों पर अमल करने की ज़रूरत थी। श्रू-श्रूक में ख्याल था कि यह काम महज चंद महीनों का है।

of India was set up in January 1950. Sukumar Sen became the first **Chief Election** Commissioner. The country's first general elections were expected sometime in 1950 itself.

The Election Commission भारत के चुनाव आयोग का गठन 1950 के जनवरी में हुआ। सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बने। उम्मीद की जा रही थी कि देश का पहला आम चुनाव 1950 में ही किसी वक्त हो जाएगा।

But the Election Commission discovered that it was not going to be easy to hold a free and fair election in a country of India's size. Holding an election required delimitation or drawing the boundaries of the electoral constituencies. It also required preparing the electoral rolls, or the list of all the citizens eligible to vote. Both these tasks took a lot of time. When the first draft of the rolls was published, it was discovered that the names of nearly 40 lakh women were not recorded in the list. They were simply listed as "wife of ..." or "daughter of ...". The Election **Commission refused to accept** these entries and ordered a revision if possible and deletion if necessary. Preparing for the first general election was a mammoth

बहरहाल, चुनाव आयोग ने पाया कि भारत के आकार को देखते हुए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष आम चुनाव कराना कोई आसान मामला नहीं है। चुनाव कराने के लिए चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन ज़रूरी था। फिर, मतदाता-सूची यानी मताधिकार प्राप्त वयस्क व्यक्तियों की सूची बनाना भी आवश्यक था। इन दोनों कामों में बहुत सारा समय लगा। मतदाता-सूचियों का जब पहला प्रारूप प्रकाशित हुआ तो पता चला कि इसमें 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज़ होने से रह गए हैं। इन महिलाओं को 'अलां की बेटी' 'फलां की बीवी'.. .. के रूप में दर्ज़ किया गया था। चुनाव आयोग ने एसी प्रविष्टियों को मानने से इनकार कर दिया। आयोग ने फ़ैसला किया कि संभव हो तो इसका पुनरावलोकन किया जाए और ज़रूरी लगे तो एसी प्रविष्टियों को हटाया जाए। यह अपने आप में हिमालय की चढ़ाई जैसा दुष्कर काम था।

No election on this scale had ever been conducted in the world before. At that time there were 17 crore eligible voters, who had to elect about 3,200 MLAs and 489 Members of Lok Sabha. Only 15 per cent of these eligible voters were literate. Therefore the Election **Commission had to think of** some special method of voting. The Election **Commission trained over 3** lakh officers and polling staff to conduct the elections.

इतने बड़े पैमाने का एसा काम दुनिया में अब तक नहीं हुआ था। उस वक्त देश में 17 करोड मतदाता थे। इन्हें 3200 विधायक और लोकसभा के लिए 489 सांसद चुनने थे। इन मतदाताओं में महज 15 फीसदी साक्षर थे। इस कारण चुनाव आयोग को मतदान की विशेष पद्धति के बारे में भी सोचना पड़ा। चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए 3 लाख से ज्यादा अधिकारियों और चुनावकर्मियों को प्रशिक्षित किया।

It was not just the size of the country and the electorate that made this election unusual. The first general election was also the first big test of democracy in a poor and illiterate country. Till then democracy had existed only in the prosperous countries, mainly in Europe and North America, where nearly everyone was literate. By that time many countries in **Europe had not given voting** rights to all women. In this context India's experiment with universal adult franchise appeared very

देश के विशाल आकार और मतदाताओं की भारी-भरकम संख्या के लिहाज़ से ही पहला आम चुनाव अनुठा नहीं था, बल्कि मतदाताओं की एक बड़ी तादाद गरीब और अनपढ लोगों की थी और एसे माहौल में यह चुनाव लोकतंत्र के लिए परीक्षा की कठिन घड़ी था। इस वक्त तक लोकतंत्र सिर्फ धनी देशों में ही कायम था। उस समय यरोप के बहुतेरे देशों में महिलाओं को मताधिकार नहीं मिला था। एसे में हिंदुस्तान में सार्वभौम मताधिकार पर अमल हुआ और यह अपने आप में बड़ा जोखिम भरा प्रयोग था।

An Indian editor called it "the biggest gamble in history". Organiser, a magazine, wrote that Jawaharlal Nehru "would live to confess the failure of universal adult franchise in India". A British member of the Indian Civil Service claimed that "a future and more enlightened age will view with astonishment the absurd farce of recording the votes of millions of illiterate people".

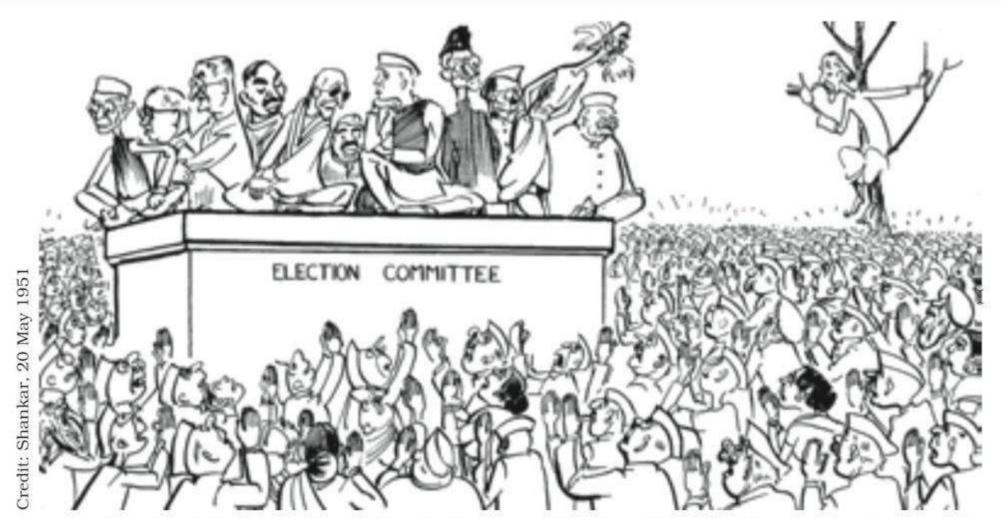
एक हिंदुस्तानी संपादक ने इसे "इतिहास का सबसे बड़ा जुआ" करार दिया। 'आर्गनाइजर' नाम की पत्रिका ने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू "अपने जीवित रहते ही यह देख लेंगे और पछताएँगे कि भारत में सार्वभौम मताधिकार असफल रहा।" इंडियन सिविल सर्विस के एक अँग्रेज़ नुमाइंदे का दावा था कि "आने वाला वक्त और अब से कहीं ज्यादा जानकार दौर बड़े विस्मय से लाखों अनपढ लोगों के मतदान की यह बेह्दी नौटंकी देखेगा।"

The elections had to be postponed twice and finally held from October 1951 to February 1952. But this election is referred to as the 1952 election since most parts of the country voted in January 1952. It took six months for the campaigning, polling and counting to be completed. **Elections were competitive** there were on an average more than four candidates for each seat. The level of participation was encouraging - more than half the eligible voters turned out to vote on the day of elections. When the results were declared these were accepted as fair even by the losers. The Indian experiment

चुनावों को दो बार स्थगित करना पड़ा और आखिरकार 1951 के अक्तूबर से 1952 के फरवरी तक चुनाव हुए। बहरहाल, इस चुनाव को अमूमन 1952 का चुनाव ही कहा जाता है क्योंकि देश के अधिकांश हिस्सों में मतदान 1952 में ही हुए। चुनाव अभियान, मतदान और मतगणना में कुल छह महीने लगे। चुनावों में उम्मीदवारों के बीच मुकाबला भी हुआ। औसतन हर सीट के लिए चार उम्मीदवार चुनाव के मैदान में थे। लोगों ने इस चुनाव में बढ्- चढ्कर हिस्सेदारी की। कुल मतदाताओं में आधे से अधिक ने मतदान के दिन अपना वोट डाला। चुनावों के परिणाम घोषित हुए तो हारने वाले उम्मीदवारों ने भी इन परिणामों को निष्पक्ष बताया। सार्वभौम मताधिकार के इस प्रयोग ने आलोचकों का मुँह बंद कर दिया।

The Times of India held that the polls have "confounded all those sceptics who thought the introduction of adult franchise too risky an experiment in this country". The Hindustan Times claimed that "there is universal agreement that the Indian people have conducted themselves admirably in the largest experiment in democratic elections in the history of the world". Observers outside India were equally impressed. India's general election of 1952 became a landmark in the history of democracy all over the world. It was no longer possible to argue that democratic elections could not be held in conditions of poverty or lack of education. It

टाइम्स ऑफ इंडिया ने माना कि इन चुनावों ने "उन सभी आलोचकों के संदेहों पर पानी फेर दिया है जो सार्वभौम मताधिकार की इस श्रु आत को इस देश के लिए जोखिम का सौदा मान रहे थे।" देश से बाहर के पर्यवेक्षक भी हैरान थे। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा- "यह बात हर जगह मानी जा रही है कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को बखूबी अंजाम दिया।" 1952 का आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। अब यह दलील दे पाना संभव नहीं रहा कि लोकतांत्रिक चुनाव गरीबी अथवा अशिक्षा के माहौल में नहीं कराए जा सकते। यह बात साबित हो गई कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र पर अमल किया जा सकता है।



A cartoonist's impression of the election committee formed by the Congress to choose party candidates in 1951. On the committee, besides Nehru: Morarji Desai, Rafi Ahmed Kidwai, Dr B.C. Roy, Kamaraj Nadar, Rajagopalachari, Jagjivan Ram, Maulana Azad, D.P. Mishra, P.D. Tandon and Govind Ballabh Pant.

1951 में कांग्रेस द्वारा पार्टी उम्मीदवार चुनने के लिए बनाई गई चुनाव सिमिति पर कार्टूनिस्ट का एक नज़िरया। सिमिति में नेहरू के अलावा मोरारजी देसाई, रफ़ी अहमद किदवई, डाॅ. बी.सी. राॅय, कामराज नाडार, राजगोपालाचारी, जगजीवन राम, मौलाना आज़ाद, डी.पी. मिश्रा, पी.डी. टंडन और गोविन्द बल्लभ पंत दिखाई दे रहे हैं।

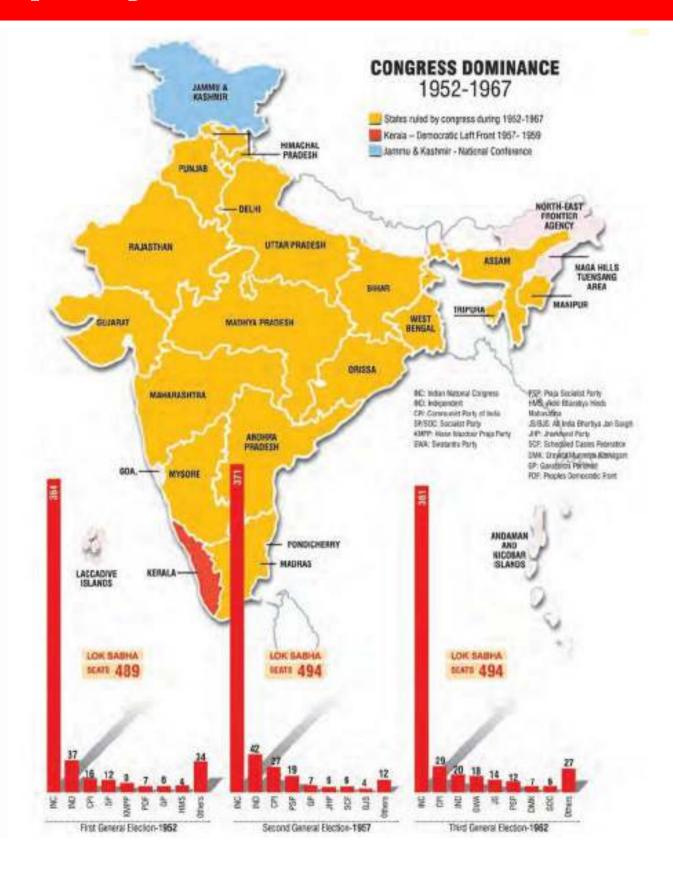
Congress dominance in the first three general elections

The results of the first general election did not surprise anyone. The Indian National **Congress was expected to win** this election. The Congress party, as it was popularly known, had inherited the legacy of the national movement. It was the only party then to have an organisation spread all over the country. And finally, in Jawaharlal Nehru, the party had the most popular and charismatic leader in Indian politics. He led the Congress campaign and toured through the country. When the final results were declared, the

पहले तीन चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व पहले आम चुनाव के नतीजों से शायद ही किसी को अचंभा हुआ हो। आशा यही थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस चुनाव में जीत जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लोकप्रचलित नाम कांग्रेस पार्टी था और इस पार्टी को स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल थी। तब के दिनों में यही एकमात्र पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में था। फिर, इस पार्टी में खुद जवाहरलाल नेहरू थे जो भारतीय राजनीति के सबसे करिश्माई और लोकप्रिय नेता थे। नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान की अगुआई की और पूरे देश का दौरा किया। जब चुनाव परिणाम घोषित हुए तो कांग्रेस पार्टी की भारी-भरकम जीत से बहुतों को आश्चर्य हुआ।

The party won 364 of the 489 seats in the first Lok Sabha and finished way ahead of any other challenger. The **Communist Party of India that** came next in terms of seats won only 16 seats. The state elections were held with the Lok Sabha elections. The Congress scored big victory in those elections as well. It won a majority of seats in all the states except Travancore-Cochin (part of today's Kerala), **Madras and Orissa. Finally** even in these states the **Congress formed the** government. So the party ruled all over the country at the national and the state level. As expected, Jawaharlal Nehru

इस पार्टी ने लोकसभा के पहले चुनाव में कुल 489 सीटों में 364 सीटें जीतीं और इस तरह वह किसी भी प्रतिद्वंद्वी से चुनावी दौड में बहुत आगे निकल गई। जहां तक सीटों पर जीत हासिल करने का सवाल है, पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर रही। उसे कुल 16 सीट हासिल हुइं। लोकसभा के चुनाव के साथ-साथ विधानसभा के भी चुनाव कराए गए थे। कांग्रेस पार्टी को विधानसभा के चुनावों में भी बड़ी जीत हासिल हुई। त्रावणकोर-कोचीन (आज के केरल का एक हिस्सा), मद्रास और उड़ीसा को छोड़कर सभी राज्यों में कांग्रेस ने अधिकतर सीटों पर जीत दर्ज़ की। आखिरकार इन तीन राज्यों में भी कांग्रेस की ही सरकार बनी। इस तरह राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का शासन कायम हुआ। उम्मीद के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू पहले आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बने।



A look at the electoral map on the previous page would give you a sense of the dominance of the Congress during the period 1952-1962. In the second and the third general elections, held in 1957 and 1962 respectively, the Congress maintained the same position in the Lok Sabha by winning three-fourth of the seats. None of the opposition parties could win even one-tenth of the number of seats won by the Congress. In the state assembly elections, the Congress did not get majority in a few cases. The most significant of these cases was in Kerala in 1957 when a coalition led by the CPI formed the government. Apart from

यहां एक चुनावी मानचित्र दिया गया है। इस पर एक नज़र दौड़ाने से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि 1952-1962 के बीच कांग्रेस पार्टी किस कदर हावी थी। दूसरा आम चुनाव 1957 में और तीसरा 1962 में हुआ। इन चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में अपनी पुरानी स्थिति बरकरार रखी और उसे तीन-चौथाई सीटें मिली। कांग्रेस पार्टी ने जितनी सीटें जीती थीं उसका दशांश भी कोई विपक्षी पार्टी नहीं जीत सकी। विधानसभा के चुनावों में कहीं-कहीं कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। एसा ही एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण केरल का है। 1957 में केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुआई में एक गठबंधन सरकार बनी। एसे एकाध मामलों को अपवाद मान लें तो कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों पर कांग्रेस पार्टी का पूरा नियंत्रण था।

The extent of the victory of the Congress was artificially boosted by our electoral system. The Congress won three out of every four seats but it did not get even half of the votes. In 1952, for example, the Congress obtained 45 per cent of the total votes. But it managed to win 74 per cent of the seats. The Socialist Party, the second largest party in terms of votes,

कांग्रेस पार्टी की जीत का यह आँकड़ा और दायरा हमारी चुनाव-प्रणाली के कारण भी बढ़ा- चढ़ा दिखता है। चुनाव प्रणाली के कारण कांग्रेस पार्टी की जीत को अलग से बढाव मिला। मिसाल के लिए, 1952 में कांग्रेस पार्टी को कुल वोटों में से मात्र 45 प्रतिशत वोट हासिल हुए थे लेकिन कांग्रेस को 74 फीसदी सीटें हासिल हुईं। सोशलिस्ट पार्टी वोट हासिल करने के लिहाज़ से दूसरे नंबर पर रही।

secured more than 10 per cent of the votes all over the country. But it could not even win three per cent of the seats. How did this happen? For this, you need to recall the discussion about the first-pastthe-post method in your textbook, Indian **Constitution at Work last** year.

उसे 1952 के चुनाव में पूरे देश में कुल 10 प्रतिशत वोट मिले थे लेकिन यह पार्टी 3 प्रतिशत सीटें भी नहीं जीत पायी। आखिर यह हुआ कैसे? पिछले साल 'भारतीय संविधान : सिद्धान्त और व्यवहार' नामक किताब में आपने 'सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत' के बारे में पढ़ा था। इससे जुड़ी चर्चा को अगर याद करें तो आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा।

In this system of election, that has been adopted in our country, the party that gets more votes than others tends to get much more than its proportional share. That is exactly what worked in favour of the Congress. If we add up the votes of all the non-Congress candidates it was more than the votes of the Congress. But the non-Congress votes were divided between different rival parties and candidates. So the Congress was still way ahead of the opposition and managed to win.

हमारे देश की चुनाव-प्रणाली में 'सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत' के तरीके को अपनाया गया है। एसे में अगर कोई पार्टी बाकियों की अपेक्षा थोड़े ज्यादा वोट हासिल करती है तो दूसरी पार्टियों को प्राप्त वोटों के अनुपात की तुलना में उसे कहीं ज्यादा सीटें हासिल होती हैं। यही चीज कांग्रेस पार्टी के पक्ष में साबित हुई। अगर हम सभी गैर-कांग्रेसी उम्मीदवारों के वोट जोड दें तो वह कांग्रेस पार्टी को हासिल कुल वोट से कहीं ज्यादा होंगे। लेकिन गैर-कांग्रेसी वोट विभिन्न प्रतिस्पर्धो पार्टियों और उम्मीदवारों में बँट गए। इस तरह कांग्रेस बाकी पार्टियों की तुलना में आगे रही और उसने ज्यादा सीटें जीतीं।

Communist victory in Kerala

As early as in 1957, the **Congress party had the bitter** taste of defeat in Kerala. In the assembly elections held in March 1957, the Communist Party won the largest number of seats in the Kerala legislature. The party won 60 of the 126 seats and had the support of five independents. The governor invited E. M. S. Namboodiripad, the leader of the Communist legislature party, to form the ministry. For the first time in the world, a **Communist party government** had come to power through democratic elections.

केरल में कम्युनिस्टों की जीत 1957 में ही कांग्रेस पार्टी को केरल में

हार का स्वाद चखना पड गया था। 1957 के मार्च महीने में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें कम्युनिस्ट पार्टी को केरल की विधानसभा के लिए सबसे ज्यादा सीटें मिलीं। कम्युनिस्ट पार्टी को कुल 126 में से 60 सीटें हासिल हुई और पाँच स्वतंत्र उम्मीदवारों का भी समर्थन इस पार्टी को प्राप्त था। राज्यपाल ने कम्युनिस्ट विधायक दल के नेता ई.एम.एस. नम्बूदरीपाद को सरकार बनाने का न्यौता दिया। दुनिया में यह पहला अवसर था जब एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनावों के जरिए बनी।

On losing power in the State, the Congress party began a 'liberation struggle' against the elected government. The CPI had come to power on the promise of carrying out radical and progressive policy measures. The Communists claimed that the agitation was led by vested interests and religious organisations. In 1959 the Congress government at the Centre dismissed the **Communist government in** Kerala under Article 356 of the Constitution. This decision proved very controversial and was widely cited as the first instance of the misuse of constitutional emergency

केरल में सत्ता से बेदखल होने पर कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचित सरकार के खिलाफ 'मुक्ति संघर्ष' छेड दिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में इस वायदे के साथ आई थी कि वह कुछ क्रांतिकारी तथा प्रगतिशील नीतिगत पहल करेगी। कम्युनिस्टों का कहना था कि इस संघर्ष की अगुआई निहित स्वार्थ और धार्मिक संगठन कर रहे हैं। 1959 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया। यह फ़ैसला बड़ा विवादास्पद साबित हुआ। संविधान-प्रदत्त आपात्कालीन शक्तियों के दुरुपयोग के पहले उदाहरण के रूप में इस फ़ैसले का बार-बार उपयोग किया गया।

The origins of the Socialist Party can be traced back to the mass movement stage of the Indian **National Congress in the pre**independence era. The Congress **Socialist Party (CSP) was formed** within the Congress in 1934 by a group of young leaders who wanted a more radical and egalitarian Congress. In 1948, the **Congress amended its** constitution to prevent its members from having a dual party membership. This forced the Socialists to form a separate **Socialist Party in 1948. The** Party's electoral performance caused much disappointment to its supporters. Although the Party had presence in most of the states of India, it could achieve electoral success only in a few

सोशलिस्ट पार्टी की जड़ों को आज़ादी से पहले के उस वक्त में ढूँढा जा सकता है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जनआंदोलन चला रही थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन खुद कांग्रेस के भीतर 1934 में युवा नेताओं की एक टोली ने किया था। ये नेता कांग्रेस को ज्यादा-से-ज्यादा परिवर्तनकामी और समतावादी बनाना चाहते थे। 1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान में बदलाव किया। यह बदलाव इसलिए किया गया था ताकि कांग्रेस के सदस्य दोहरी सदस्यता न धारण कर सकें। इस वजह से कांग्रेस के समाजवादियों को मजबूरन 1948 में अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी बनानी पड़ी। सोशलिस्ट पार्टी चुनावों में कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। इससे पार्टी के समर्थकों को बड़ी निराशा हुई। हालाँकि सोशलिस्ट पार्टी की मौजूदगी हिंदुस्तान के अधिकतर राज्यों में थी लेकिन पार्टी को चुनावों में छिटपुट सफलता ही मिली।

The socialists believed in the ideology of democratic socialism which distinguished them both from the Congress as well as from the Communists. They criticised the Congress for favouring capitalists and landlords and for ignoring the workers and the peasants. But the socialists faced a dilemma when in 1955 the Congress declared its goal to be the socialist pattern of society. Thus it became difficult for the socialists to present themselves as an effective alternative to the Congress. Some of them, led by Rammanohar Lohia, increased their distance from and criticism of the Congress party. Some others like Asoka Mehta

समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा में विश्वास करते थे और इस आधार पर वे कांग्रेस तथा साम्यवादी (कम्युनिस्ट) दोनों से अलग थे। वे कांग्रेस की आलोचना करते थे कि वह पूँजीपतियों और जमींदारों का पक्ष ले रही है और मज़दूरों-किसानों की उपेक्षा कर रही है। समाजवादियों को 1955 में दुविधा की स्थिति का सामना करना पड़ा क्योंकि कांग्रेस ने घोषणा कर दी कि उसका लक्ष्य समाजवादी बनावट वाले समाज की रचना है। एसे में समाजवादियों के लिए खुद को कांग्रेस का कारगर विकल्प बनाकर पेश करना मुश्किल हो गया। राममनोहर लोहिया के नेतृत्व में कुछ समाजवादियों ने कांग्रेस से अपनी दूरी बढ़ायी और कांग्रेस की आलोचना की। कुछ अन्य समाजवादियों मसलन अशोक मेहता ने कांग्रेस से हल्के-फुल्के सहयोग की तरफदारी की।

The Socialist Party went through many splits and reunions leading to the formation of many socialist parties. These included the Kisan Mazdoor Praja Party, the Praja Socialist Party and Samyukta Socialist Party. Jayaprakash Narayan, Achyut Patwardhan, Asoka Mehta, Acharya Narendra Dev, Rammanohar Lohia and S.M. Joshi were among the leaders of the socialist parties. Many parties in contemporary India, like the Samajwadi Party, the Rashtriya Janata Dal, Janata Dal (United) and the Janata Dal (Secular) trace their origins to the Socialist Party.

सोशलिस्ट पार्टी के कई टुकड़े हुए और कुछ मामलों में बहुधा मेल भी हुआ। इस प्रक्रिया में कई समाजवादी दल बने। इन दलों में, किसान मज़दूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का नाम लिया जा सकता है। जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवधन, अशोक मेहता. आचार्य नरेन्द्र देव. राममनोहर लोहिया और एस.एम. जोशी समाजवादी दलों के नेताओं में प्रमुख थे। मौजूदा हिंदुस्तान के कई दलों जैसे समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल (य्नाइटेड) और जनता दल (सेक्युलर) पर सोशलिस्ट पार्टी की छाप देखी जा सकती है।

Nature Congress dominance

India is not the only country to have experienced the dominance of one party. If we look around the world, we find many other examples of one-party dominance. But there is a crucial difference between these and the Indian experience. In the rest of the cases the dominance of one party was ensured by compromising democracy. In some countries like China, Cuba and Syria the constitution permits only a single party to rule the country. Some others like Myanmar, Belarus, Egypt, and Eritrea are effectively one-party states due to legal and military measures. Until a few years ago, Mexico, South Korea and Taiwan were also effectively one-party dominant states.

कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति

भारत ही एकमात्र एसा देश नहीं है जो एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरा हो। अगर हम दुनिया के बाकी मुल्कों पर नजर दौड़ाएँ तो हमें एक पार्टी के प्रभुत्व के बहुत-से उदाहरण मिलेंगे। बहरहाल, बाकी मुल्कों में एक पार्टी के प्रभुत्व और भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व के बीच एक बड़ा भारी फर्क है। बाकी मुल्कों में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत पर कायम हुआ। कुछ देशों मसलन चीन, क्यूबा और सीरिया के संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी को देश के शासन की अनुमति दी गई है। कुछ और देशों जैसे म्यांमार, बेलारूस और इरीटिया में एक पार्टी का प्रभुत्व कानूनी और सैन्य उपायों के चलते कायम हुआ है। अब से कुछ साल पहले तक मैक्सिको, दक्षिण कोरिया और ताईवान भी एक पार्टी के प्रभुत्व वाले देश थे।

What distinguished the dominance of the Congress party in India from all these cases was it happened under democratic conditions. Many parties contested elections in conditions of free and fair elections and yet the **Congress managed to win** election after election. This was similar to the dominance the African National Congress has enjoyed in South Africa after the end of apartheid.

भारत में कायम एक पार्टी का प्रभुत्व इन उदाहरणों से कहीं अलग है। यहां एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतांत्रिक स्थितियों में कायम हुआ। अनेक पार्टियों ने मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के माहौल में एक-दूसरे से होड की और तब भी कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक चुनाव जीतती गई। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की समाप्ति के बाद अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का भी कुछ एसा ही दबदबा कायम हुआ है। भारत का उदाहरण बहुत कुछ दक्षिण अफ्रीका से मिलता-जुलता है।

The roots of this extraordinary success of the Congress party go back to the legacy of the freedom struggle. Congress was seen as inheritor of the national movement. Many leaders who were in the forefront of that struggle were now contesting elections as **Congress candidates. The Congress was already a very** well-organised party and by the time the other parties could even think of a strategy, the **Congress had already started** its campaign. In fact, many parties were formed only around Independence or after that. Thus, the Congress had the 'first off the blocks'

कांग्रेस पार्टी की इस असाधारण सफलता की जड़ें स्वाधोनता-संग्राम की विरासत में हैं। कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन के वारिस के रूप में देखा गया। आज़ादी के आंदोलन में अग्रणी रहे अनेक नेता अब कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड रहे थे। कांग्रेस पहले से ही एक सुसंगठित पार्टी थी। बाकी दल अभी अपनी रणनीति सोच ही रहे होते थे कि कांग्रेस अपना अभियान शुरू कर देती थी। दरअसल, अनेक पार्टियों का गठन स्वतंत्रता के समय के आस-पास अथवा उसके बाद में हुआ। कांग्रेस को 'अव्वल और एकलौता' होने का फायदा मिला।

By the time of Independence the party had not only spread across the length and breadth of the country as we had seen in the maps but also had an organisational network down to the local level. Most importantly, as the Congress was till recently a national movement, its nature was allinclusive. All these factors contributed to the dominance of the Congress party.

आज़ादी के वक्त तक यह पार्टी देश में चहुं ओर फैल चुकी थी। आप यह बात दिए गए मानचित्र में देख चुके हैं। फिर, इस पार्टी के संगठन का नेटवर्क स्थानीय स्तर तक पहुँच चुका था। सबसे बड़ी बात यह थी कि कांग्रेस हाल-फिलहाल तक आज़ादी के आंदोलन की अगुआ रही थी और उसकी प्रकृति सबको समेटकर मेलजोल के साथ चलने की थी।

Congress as social and ideological coalition

You have already studied the history of how Congress evolved from its origins in 1885 as a pressure group for the newly educated, professional and commercial classes to a mass movement in the twentieth century. This laid the basis for its eventual transformation into a mass political party and its subsequent domination of the political system. Thus the Congress began as a party dominated by the English speaking, upper caste, upper middle-class and urban elite.

कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में आप यह बात पढ चुके हैं कि कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ था। उस वक्त यह नवशिक्षित. कामकाजी और व्यापारिक वर्गों का एक हित-समूह भर थी लेकिन 20वीं सदी में इसने जनआंदोलन का रूप ले लिया। इस वजह से कांग्रेस ने एक जनव्यापी राजनीतिक पार्टी का रूप लिया और राजनीतिक-व्यवस्था में इसका दबदबा कायम हुआ। शुरू-शुरू में कांग्रेस में अँग्रेज़ीदां, अगड़ी जाति, ऊँचले मध्यवर्ग और शहरी अभिजन का बोलबाला था।

But with every civil disobedience movement it launched, its social base widened. It brought together diverse groups, whose interests were often contradictory. Peasants and industrialists, urban dwellers and villagers, workers and owners, middle, lower and upper classes and castes, all found space in the Congress. Gradually, its leadership also expanded beyond the upper caste and upper class professionals to agriculture based leaders with a rural orientation.

लेकिन कांग्रेस ने जब भी सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलन चलाए उसका सामाजिक आधार बढा। कांग्रेस ने परस्पर विरोधी हितों के कई समूहों को एक साथ जोडा। कांग्रेस में किसान और उद्योगपति, शहर के बाशिंदे और गाँव के निवासी, मज़दूर और मालिक एवं मध्य, निम्न और उच्च वर्ग तथा जाति सबको जगह मिली। धोरे-धोरे कांग्रेस का नेतृवर्ग भी विस्तृत हुआ। इसका नेतृवर्ग अब उच्च वर्ग या जाति के पेशेवर लोगों तक ही सीमित नहीं रहा। इसमें खेती-किसानी की बुनियाद वाले तथा गाँव-गिरान की तरफ़ रुझान रखने वाले नेता भी उभरे।

the Congress was transformed into a rainbowlike social coalition broadly representing India's diversity in terms of classes and castes, religions and languages and various interests.

By the time of Independence, आज़ादी के समय तक कांग्रेस एक सतरंगे सामाजिक गठबंधन की शक्ल अख़्तियार कर चुकी थी और वर्ग, जाति, धर्म. भाषा तथा अन्य हितों के आधार पर इस सामाजिक गठबंधन से भारत की विविधता की नुमाइंदगी हो रही थी।

Many of these groups merged their identity within the Congress. Very often they did not and continued to exist within the Congress as groups and individuals holding different beliefs. In this sense the Congress was an ideological coalition as well. It accommodated the revolutionary and pacifist, conservative and radical, extremist and moderate and the right, left and all shades of the centre.

इनमें से अनेक समूहों ने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ एकमेक कर दिया। कई बार यह भी हुआ कि किसी समूह ने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ एकसार नहीं किया और अपने-अपने विश्वासों को मानते हुए बतौर एक व्यक्ति या समूह के कांग्रेस के भीतर बने रहे। इस अर्थ में कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन भी थी। कांग्रेस ने अपने अंदर क्रांतिकारी और शांतिवादी. कंजरवेटिव और रेडिकल. गरमपंथी और नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी और हर धारा के मध्यमार्गियों को समाहित किया।

The Congress was a 'platform' for numerous groups, interests and even political parties to take part in the national movement. In pre-Independence days, many organisations and parties with their own constitution and organisational structure were allowed to exist within the Congress.

कांग्रेस एक मंच की तरह थी, जिस पर अनेक समूह, हित और राजनीतिक दल तक आ जुटते थे और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते थे। आज़ादी से पहले के वक्त में अनेक संगठन और पार्टियों को कांग्रेस में रहने की इजाज़त थी।

Some of these, like the **Congress Socialist Party,** later separated from the **Congress and became** opposition parties. Despite differences regarding the methods, specific programmes and policies the party managed to contain if not resolve differences and build a consensus.

हालाँकि इन संगठनों और पार्टियों के अपने-अपने संविधान थे। इनका सांगठनिक ढाँच भी अलग था। इनमें से कुछ (मसलन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी) बाद में कांग्रेस से अलग हो गए और विपक्षी दल बने। किसी खास पद्धति. कार्यक्रम या नीति को लेकर मौजूद मतभेदों को कांग्रेस पार्टी सुलझा भले न पाए लेकिन उन्हें अपने आप में मिलाए रखती थी और एक आम सहमति कायम कर ले जाती थी।

Tolerance and management of factions

This coalition-like character

of the Congress gave it an unusual strength. Firstly, a coalition accommodates all those who join it. Therefore, it has to avoid any extreme position and strike a balance on almost all issues. **Compromise and** inclusiveness are the hallmarks of a coalition. This strategy put the opposition in a difficulty. Anything that the opposition wanted to say, would also find a place in the programme and ideology of the Congress.

गुटों में तालमेल और सहनशीलता कांग्रेस के गठबंधनी स्वभाव ने उसे एक असाधारण ताकत दी। पहली बात तो यही कि जो भी आए. गठबंधन उसे अपने में शामिल कर लेता है। इस कारण गठबंधन को अतिवादी रुख अपनाने से बचना होता है और हर मसले पर संतुलन को साधकर चलना पड़ता है। सुलह-समझौते के रास्ते पर चलना और सर्व-समावेशी होना गठबंधन की विशेषता होती है। इस रणनीति की वजह से विपक्ष कठिनाई में पड़ा। विपक्ष कोई बात कहना चाहे तो कांग्रेस की विचारधारा और कार्यक्रम में उसे तुरंत जगह मिल जाती थी।

Secondly, in a party that has the nature of a coalition, there is a greater tolerance of internal differences and ambitions of various groups and leaders are accommodated. The **Congress did both these** things during the freedom struggle and continued doing this even after Independence. That is why, even if a group was not happy with the position of the party or with its share of power, it would remain inside the party and fight the other groups rather than leaving the party and becoming an

दूसरे, अगर किसी पार्टी का स्वभाव गठबंधनी हो तो अंदरूनी मतभेदों को लेकर उसमें सहनशीलता भी ज्यादा होती है। विभिन्न समूह और नेताओं की महत्त्वाकांक्षाओं की भी उसमें समाई हो जाती है। कांग्रेसने आजादी की लड़ाई के दौरान इन दोनों ही बातों पर अमल किया था और आज़ादी मिलने के बाद भी इस पर अमल जारी रखा। इसी कारण, अगर कोई समूह पार्टी के रुख से अथवा सत्ता में प्राप्त अपने हिस्से से नाखुश हो तब भी वह पार्टी में ही बना रहता था। पार्टी को छोड़कर विपक्षी की भूमिका अपनाने की जगह पार्टी में मौजूद किसी दूसरे समूह से लड़ने को बेहतर समझता था।

These groups inside the party are called factions. The coalitional nature of the Congress party tolerated and in fact encouraged various factions. Some of these factions were based on ideological considerations but very often these factions were rooted in personal ambitions and rivalries. Instead of being a weakness, internal factionalism became a strength of the **Congress. Since there was** room within the party for various factions to fight with each other, it meant that leaders representing different interests and ideologies remained within the Congress rather than an out and form a

पार्टी के अंदर मौजूद विभिन्न समूह गुट कहे जाते हैं। अपने गठबंधनी स्वभाव के कारण कांग्रेस विभिन्न गुटों के प्रति सहनशील थी और इस स्वभाव से विभिन्न गुटों को बढ़ावा भी मिला। कांग्रेस के विभिन्न गुटों में से कुछ विचारधारात्मक सरोकारों की वजह से बने थे। लेकिन अकसर गुटों के बनने के पीछे व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा तथा प्रतिस्पर्धा की भावना भी काम करती थी। एसे में अंदरूनी गुटबाजी कांग्रेस की कमज़ोरी बनने की बजाय उसकी ताकत साबित हुई। चूंकि पार्टी के भीतर विभिन्न गुटों की आपसी होड के लिए गुंजाइश थी इसलिए विभिन्न हित और विचारधाराओं की नुमाइंदगी कर रहे नेता कांग्रेस के भीतर ही बने रहे। पार्टी से बाहर निकलकर नई पार्टी बनाने को इन्होंने बेहतर नहीं समझा।

Most of the state units of the Congress were made up of numerous factions. The factions took different ideological positions making the Congress appear as a grand centrist party. The other parties primarily attempted to influence these factions and thereby indirectly influenced policy and decision making from the "margins". They were far removed from the actual exercise of authority. They were not alternatives to the ruling party;

कांग्रेस की अधिकतर प्रांतीय इकाइयों विभिन्न गुटों को मिलाकर बनी थीं। ये गुट अलग-अलग विचारधारात्मक रुख अपनाते थे और कांग्रेस एक भारी -भरकम मध्यमार्गी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आती थी। दूसरी पार्टियां मुख्यत: कांग्रेस के इस या उस गुट को प्रभावित करने की कोशिश करती थीं। इस तरह बाकी पार्टियां हाशिए पर रहकर ही नीतियों और फैसलों को अप्रत्यक्ष रीति से प्रभावित कर पाती थीं। ये पार्टियां सत्ता के वास्तविक इस्तेमाल से कोसों दूर थीं। शासक दल का कोई विकल्प नहीं था।

instead they constantly pressurised and criticised, censured and influenced the Congress. The system of factions functioned as balancing mechanism within the ruling party. Political competition therefore took place within the Congress. In that sense, in the first decade of electoral competition the Congress acted both as the ruling party as well as the opposition. That is why this period of Indian politics has been described as the 'Congress system'.

इसके बावजूद विपक्षी पार्टियां लगातार कांग्रेस की आलोचना करती थीं, उस पर दबाव डालती थीं और इस क्रम में उसे प्रभावित करती थीं। गुटों की मौजूदगी की यह प्रणाली शासक-दल के भीतर संतुलन साधने के एक औजार की तरह काम करती थी। इस तरह राजनीतिक होड कांग्रेस के भीतर ही चलती थी। इस अर्थ में देखें तो चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस ने शासक-दल की भूमिका निभायी और विपक्ष की भी। इसी कारण भारतीय राजनीति के इस कालखंड को 'कांग्रेस-प्रणाली' कहा जाता है।

Emergence of opposition parties

As we have noted above, it is not that India did not have opposition parties during this period. While discussing the results of the elections, we have already come across the names of many parties other than the Congress. Even then India had a larger number of diverse and vibrant opposition parties than many other multi-party democracies. Some of these had come into being even before the first general election of 1952. Some of these parties played an important part in the politics of the country in the 'sixties and 'seventies. The roots of almost all the non-Congress parties of today can be traced to one or

विपक्षी पार्टियों का उद्भव

जैसा कि हमने ऊपर देखा, एसा नहीं था कि इस दौर में भारत में विपक्षी पार्टियां नहीं थीं। चुनाव-परिणामों की चर्चा में हमारे सामने कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों के नाम भी आए। बहुदलीय लोकतंत्र वाले अन्य अनेक देशों की तुलना में उस वक्त भी भारत में बहुविध और जीवन्त विपक्षी पार्टियां थीं। इनमें से कई पार्टियां 1952 के आम चुनावों से कहीं पहले बन चुकी थीं। इनमें से कुछ ने 'साठ' और 'सत्तर' के दशक में देश की राजनीति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी। आज की लगभग सभी गैर-कांग्रेसी पार्टियों की जड़ें 1950 के दशक की किसी न किसी विपक्षी पार्टी में खोजी जा सकती हैं।

All these opposition parties succeeded in gaining only a token representation in the Lok Sabha and state assemblies during this period. Yet their presence played a crucial role in maintaining the democratic character of the system. These parties offered a sustained and often principled criticism of the policies and practices of the Congress party. This kept the ruling party under check and often changed the balance of power within the Congress. By keeping democratic political alternative alive, these parties prevented the resentment with the system from turning antidemocratic. These parties also groomed the leaders who were to play a crucial role in the shaping of our country.

1950 के दशक में इन सभी विपक्षी दलों को लोकसभा अथवा विधानसभा में कहने भर को प्रतिनिधित्व मिल पाया। फिर भी, इन दलों की मौजूदगी ने हमारी शासन-व्यवस्था के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभायी। इन दलों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों और व्यवहारों की सुचिन्तित आलोचना की। इस आलोचना में सिद्धांतों का बल होता था। विपक्षी दलों ने शासक-दल पर अंकुश रखा और बहुधा इन दलों के कारण कांग्रेस पार्टी के भीतर शक्ति-संतुलन बदला। इन दलों ने लोकतांत्रिक राजनीतिक विकल्प की संभावना को जीवित रखा। एसा करके इन दलों ने व्यवस्थाजन्य रोष को लोकतंत्र-विरोधी बनने से रोका। इन दलों ने एसे नेता तैयार किए जिन्होंने आगे के समय में हमारे देश की तस्वीर को संवारने में अहम भूमिका निभायी।

In the early years there was a lot of mutual respect between the leaders of the Congress and those of the opposition. The interim government that ruled the country after the declaration of Independence and the first general election Dr. Ambedkar and Shyama **Prasad Mukherjee in the** cabinet. Jawaharlal Nehru often referred to his fondness for the Socialist Party and invited socialist leaders like Jayaprakash Narayan to join his government. This kind of personal relationship with and respect for political adversaries declined after the party competition arew more intense

श्रुआती सालों में कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच पारस्परिक सम्मान का गहरा भाव था। स्वतंत्रता की उद्घोषणा के बाद अंतरिम सरकार ने देश का शासन सँभाला था। इसके मंत्रिमंडल में डॉ. अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे included opposition leaders like विपक्षी नेता शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू अकसर सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अपने प्यार का इजहार करते थे। उन्होंने जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं को सरकार में शामिल होने का न्यौता दिया। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी से इस किस्म का निजी रिश्ता और उसके प्रति सम्मान का भाव दलगत प्रतिस्पर्धा के तेज होने के बाद लगातार कम होता गया।

Thus this first phase of democratic politics in our country was quite unique. The inclusive character of the national movement led by the **Congress enabled it to attract** different sections, groups and interests making it a broad based social and ideological coalition. The key role of the **Congress in the freedom** struggle thus gave it a head start over others. As the ability of the Congress to accommodate all interests and all aspirants for political power steadily declined, other political parties started gaining greater significance. Thus, **Congress dominance** constitutes only one phase in

इस तरह अपने देश में लोकतांत्रिक राजनीति का पहला दौर एकदम अनुठा था। राष्ट्रीय आंदोलन का चरित्र समावेशी था। इसकी अगुआई कांग्रेस ने की थी। राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरित्र के कारण कांग्रेस की तरफ विभिन्न समूह, वर्ग और हितों के लोग आकर्षित हुए। सामाजिक और विचारधारात्मक रूप से कांग्रेस एक व्यापक गठबंधन के रूप में उभरी। आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस ने मुख्य भूमिका निभायी थी और इस कारण कांग्रेस को दूसरी पार्टियों की अपेक्षा बढ़त प्राप्त थी। सत्ता पाने की लालसा रखने वाले हर व्यक्ति और हर हित-समूह को अपने अंदर समाहित करने की कांग्रेस की क्षमता जैसे-जैसे घटी वैसे-वैसे दूसरे राजनीतिक दलों को महत्त्व मिलना शुरू हुआ। इस तरह कांग्रेस का प्रभुत्व देश की राजनीति के सिर्फ़ एक दौर में रहा।

The Communist Party of India In the early 1920s communist groups emerged in different parts of India taking inspiration from the Bolshevik revolution in Russia and advocating socialism as the solution to problems affecting the country. From 1935, the **Communists worked mainly from** within the fold of the Indian **National Congress. A parting of** ways took place in December 1941, when the Communists decided to support the British in their war against Nazi Germany. **Unlike other non-Congress parties** the CPI had a well-oiled party machinery and dedicated cadre at the time of Independence. However, Independence raised different voices in the party. The basic question that troubled the

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया

1920 के दशक के शुरुआती सालों में भारत के विभिन्न हिस्सों में साम्यवादी-समूह (कम्युनिस्ट ग्रुप) उभरे। ये रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित थे और देश की समस्याओं के समाधान के लिए साम्यवाद की राह अपनाने की तरप हदारी कर रहे थे। 1935 से साम्यवादियों ने मुख्यतया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दायरे में रहकर काम किया। कांग्रेस से साम्यवादी 1941 के दिसंबर में अलग हुए। इस समय साम्यवादियों ने नाजी जर्मनी के खिलाफ लड रहे ब्रिटेन को समर्थन देने का ए हैसला किया। दूसरी गैर-कांग्रेसी पार्टियों के विपरीत कम्युनिस्ट पार्टी ऑप **ह इंडिया के पास आज़ादी के समय एक सुचारू पार्टी** मशीनरी और समर्पित कॉडर मौजूद थे। बहरहाल, आज़ादी हासिल होने पर इस पार्टी के भीतर कई स्वर उभरे। इस पार्टी के सामने मुख्य सवाल यह था कि आखिर जो आजादी देश को हासिल हुई है उसकी प्रकृति कैसी है? क्या हिंदुस्तान सचमुच आज़ाद हुआ है या यह आज़ादी झ्ठी है?

Soon after Independence, the party thought that the transfer of power in 1947 was not true independence and encouraged violent uprisings in Telangana. The Communists failed to generate popular support for their position and were crushed by the armed forces. This forced them to rethink their position. In 1951 the **Communist Party abandoned** the path of violent revolution and decided to participate in the approaching general elections. In the first general election, CPI won 16 seats and emerged as the largest opposition party. The party's support was more

concentrated in Andhra

आज़ादी के तुरंत बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विचार था कि 1947 में सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ वह सच्ची आज़ादी नहीं थी। इस विचार के साथ पार्टी ने तेलंगाना में हिंसक विद्रोह को बढ़ाव दिया। साम्यवादी अपनी बात के पक्ष में जनता का समर्थन हासिल नहीं कर सके और इन्हें सशस्त्र सेनाओं द्वारा दबा दिया गया। मज़बूरन इन्हें अपने पक्ष को लेकर पुनर्विचार करना पड़ा। 1951 में साम्यवादी पार्टी ने हिंसक क्रांति का रास्ता छोड दिया और आने वाले आम चुनावों में भाग लेने का पृ रेसला किया। पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 16 सीटें जीतीं और वह सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी। इस दल को ज्यादातर समर्थन आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और केरल में मिला।

A. K. Gopalan, S.A. Dange, E.M.S. Namboodiripad, P.C. Joshi, Ajay Ghosh and P. Sundarraya were among the notable leaders of the **CPI. The Party went** through a major split in 1964 following the ideological rift between **Soviet Union and China.** The pro-Soviet faction remained as the CPI, while the opponents formed the **CPI(M).** Both these parties continue to exist to this day.

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेताओं में ए.के. गोपालन, एस.ए. डांगे, ई.एम. एस. नम्बूदरीपाद, पी.सी. जोशी, अजय घोष और पी. सुंदरैया के नाम लिए जाते हैं। चीन और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक अंतर आने के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में एक बड़ी टूट का शिकार हुई। सोवियत संघ की विचारधारा को ठीक मानने वाले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रहे जबिक इसके विरोध में राय रखने वालों ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) या सीपीआई (एम) नाम से अलग दल बनाया। ये दोनों दल आज तक कायम हैं।

Bharatiya Jana Sangh

The Bharatiya Jana Sangh was formed in 1951 with Shyama Prasad Mukherjee as its founder-**President. Its lineage** however can be traced back to the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) and the Hindu Mahasabha before Independence.

भारतीय जनसंघ

भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक-अध्यक्ष थे। इस दल की जड़ें आजादी के पहले के समय से सिक्रय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और हिंदू महासभा में खोजी जा सकती हैं।

The Jana Sangh was different from other parties in terms of ideology and programmes. It emphasised the idea of one country, one culture and one nation and believed that the country could become modern, progressive and strong on the basis of Indian culture and traditions. The party called for a reunion of India and Pakistan in Akhand **Bharat. The party was in** forefront of the agitation to replace English with Hindi as the official language of India and was also opposed to the granting of concessions to

जनसंघ अपनी विचारधारा और कार्यक्रमों के लिहाज से बाकी दलों से भिन्न है। जनसंघ ने 'एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट' के विचार पर जोर दिया। इसका मानना था कि देश भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर आध्निक, प्रगतिशील और ताकतवर बन सकता है। जनसंघ ने भारत और पाकिस्तान को एक करके 'अखंड भारत' बनाने की बात कही। अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने के आंदोलन में यह पार्टी सबसे आगे थी। इसने धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायत देने की बात का विरोध किया।

The party was a consistent advocate of India developing nuclear weapons especially after China carried out its atomic tests in 1964.

चीन ने 1964 में अपना आण्विक-परीक्षण किया था। इसके बाद से जनसंघ ने लगातार इस बात की पैरोकारी की कि भारत भी अपने आण्विक हथियार तैयार करे।

In the 1950s Jana Sangh remained on the margins of the electoral politics and was able to secure only 3 Lok Sabha seats in 1952 elections and 4 seats in 1957 general elections to Lok Sabha. In the early years its support came mainly from the urban areas in the Hindi speaking states like Rajasthan, Madhya Pradesh, Delhi and Uttar Pradesh. The party's leaders included Shyama Prasad Mukherjee, Deen Dayal Upadhyaya and Balraj Madhok. The Bharatiya **Janata Party traces its roots** to the Bharatiya Jana Sangh.

1950 के दशक में जनसंघ चुनावी राजनीति के हाशिए पर रहा। इस पार्टी को 1952 के चुनाव में लोकसभा की तीन सीटों पर सफलता मिली और 1957 के आम चुनावों में इसने लोकसभा की 4 सीटें जीतीं। शुरुआती सालों में इस पार्टी को हिंदी-भाषी राज्यों मसलन राजस्थान. मध्य प्रदेश. दिल्ली और उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में समर्थन मिला। जनसंघ के नेताओं में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मधोक के नाम शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी की जड़ें इसी जनसंघ में हैं।

Swatantra Party - 1959

Swatantra Party was formed in August 1959 after the Nagpur resolution of the **Congress which called for** land ceilings, take-over of food grain trade by the state and adoption of cooperative farming. The party was led by old Congressmen like C. Rajagopalachari, K.M.Munshi, N.G.Ranga and Minoo Masani. The party stood out from the others in terms of its position on economic issues

स्वतंत्र पाटी -1959

कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में जमीन की हदबंदी. खाद्यान्न के व्यापार. सरकारी अधिग्रहण और सहकारी खेती का प्रस्ताव पास हुआ था। इसी के बाद 1959 के अगस्त में स्वतंत्र पार्टी अस्तित्व में आई। इस पार्टी का नेतृत्व सी. राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी, एन.जी. रंगा और मीनू मसानी जैसे पुराने कांग्रेस नेता कर रहे थे। यह पार्टी आर्थिक मसलों पर अपनी खास किस्म की पक्षध रता के कारण दूसरी पार्टियों से अलग थी।

The Swatantra Party wanted the government to be less and less involved in controlling the economy. It believed that prosperity could come only through individual freedom. It was critical of the development strategy of state intervention in the economy, centralised planning, nationalisation and the public sector. It instead favoured expansion of a free private sector. The Swatantra Party was against land ceilings in agriculture, and opposed cooperative farming and state trading.

स्वतंत्र पार्टी चाहती थी कि सरकार अर्थव्यवस्था में कम से कमतर हस्तक्षेप करे। इसका मानना था कि समृद्धि सिर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जरिए आ सकती है। स्वतंत्र पार्टी अर्थव्यवस्था में विकास के नजिए से किए जा रहे राजकीय हस्तक्षेप, केंद्रीकृत नियोजन, राष्ट्रीयकरण और अर्थव्यवस्था के भीतर सार्वजनिक-क्षेत्र की मौजूदगी को आलोचना की निगाह से देखती थी। यह पार्टी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के हित को ध्यान में रखकर किए जा रहे कराधान के भी खिलाफ थी। इस दल ने निजी क्षेत्र को खुली छूट देने की तरफदारी की। स्वतंत्र पार्टी कृषि में जमीन की हदबंदी. सहकारी खेती और खाद्यान्न के व्यापार पर सरकारी नियंत्रण के विरुद्ध थी।

It was also opposed to the progressive tax regime and demanded dismantling of the licensing regime. It was critical of the policy of non-alignment and maintaining friendly relations with the Soviet Union and advocated closer ties with the United States. The Swatantra Party gained strength in different parts of the Country by way of merger with numerous regional parties and interests. It attracted the landlords and princes who wanted to protect their land and status that was being threatened by the land reforms legislation. The industrialists and business class who were against nationalisation and the licensing policies also supported the party. Its narrow social base and the lack of a dedicated cadre of party members did not allow it to build a strong organisational network.

यह दल गुटनिरपेक्षता की नीति और सोवियत संघ से दोस्ताना रिश्ते कायम रखने को भी गलत मानती थी। इसने संयुक्त राज्य अमरीका से नजदीकी संबंध बनाने की वकालत की। अनेक क्षेत्रीय पार्टियों और हितों के साथ मेल करने के कारण स्वतंत्र पार्टी देश के विभिन्न हिस्सों में ताकतवर हुई। स्वतंत्र पार्टी की तरफ मुख्य रूप से जमींदार और राजे-महाराजे आकर्षित हुए। भूमि-सुधार के कानूनों से इनकी मिल्कियत और हैसियत को खतरा मँडरा रहा था और इससे बचने के लिए इन लोगों ने स्वतंत्र पार्टी का दामन थामा। उद्योगपित और व्यवसायी-वर्ग के लोग राष्ट्रीयकरण और लाइसेंस-नीति के खिलाफ थे। इन लोगों ने भी स्वतंत्र पार्टी का समर्थन किया। इस पार्टी का सामाजिक आधार बड़ा संकुचित था और इसके पास पार्टी-सदस्य के रूप में समर्पित कॉडर की कमी थी। इस वजह से यह पार्टी अपना मजबूत सांगठनिक नेटवर्क खड़ा नहीं कर पाई।